

[2025] 1 एस.सी.आर. 1683 : 2025 आईएनएससी 345

1. आयुक्त, बेंगलुरु विकास प्राधिकरण

2. बेंगलुरु विकास प्राधिकरण

बनाम

1. श्रीमती. रत्नम्मा

2. श्री जी अरविन्द

3. श्रीमती. राधाम्मा

(सिविल अपील संख्या 3764/2025)

03 जनवरी 2025

[सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्तिगण]

विचारणीय मुद्दा

बेंगलोर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1976 की धारा 17(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना 20.03.1999 को जारी की गई थी, जिसमें प्रतिवादियों/उनके पूर्वजों से 4 एकड़ और 15 गुंटा भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था। बेंगलोर विकास प्राधिकरण (भूमि के स्वैच्छिक समर्पण के लिए प्रोत्साहन योजना) नियम, 1989 [1989 के मूल प्रोत्साहन नियम] के तहत भूमि के अधिग्रहण और स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के संबंध में संपूर्ण लेन-देन और साथ ही बेंगलोर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1976 की धारा 19(1) के तहत कब्जा और अधिसूचना और अधिनियम की धारा 9 के तहत संशोधित प्रोत्साहन नियमों के प्रभावी होने से बहुत पहले पूरा हो गया था। दिनांक 27.11.2002. 10.03.2005 को, प्रोत्साहन नियमों के अनुसार स्थलों के आवंटन के लिए प्रतिवादियों द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। क्या 09.11.1989 को अधिसूचित प्रोत्साहन नियम जो 01.04.1989 से लागू हुए या 09.08.2005 को अधिसूचित संशोधित प्रोत्साहन नियम जो 27.11.2002 से लागू हुए, वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू होंगे।

शीर्ष टिप्पणियाँ

बेंगलोर विकास प्राधिकरण (भूमि के स्वैच्छिक समर्पण के लिए प्रोत्साहन योजना) नियम, 1989 - बेंगलोर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1976 - धारा 17(1) - प्रोत्साहन नियमों के तहत भूमि का स्वैच्छिक समर्पण - प्रोत्साहन नियमों के संदर्भ में स्थलों के आवंटन के लिए आवेदन - क्या 1989 के प्रोत्साहन नियम या संशोधित प्रोत्साहन नियम लागू होंगे:

अभिनिर्धारित: प्रतिवादियों ने जो लाभ लेने की मांग की थी, वह यह था कि चूंकि उनका आवेदन 10.03.2005 को किया गया था, संशोधित प्रोत्साहन नियम पहले ही लागू हो चुके थे और इस प्रकार संशोधित प्रोत्साहन नियमों के तहत विचार किया जाना चाहिए था, जिससे उन व्यक्तियों को भूमि आवंटन के लिए अतिरिक्त पात्रता का लाभ मिलता था, जिन्होंने स्वेच्छा से प्रोत्साहन नियमों के तहत अपनी भूमि को आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुना था - प्रतिवादी किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं, जिसे उस दिन से गिना जाना चाहिए जब स्वैच्छिक का पूरा लेनदेन प्रासंगिक कानून के तहत अधिग्रहण की शर्तों के तहत उनकी भूमि का समर्पण पूरा हो गया, जिसके बाद अधिसूचना और कब्जा सौंपने के साथ-साथ मुआवजा राशि भी जमा कर दी गई; यह सब 27.11.2002 से बहुत पहले हुआ था - वास्तव में, प्रतिवादी केवल इस कारण से अपना दावा बनाए रखने में सक्षम रहे हैं कि प्रोत्साहन नियमों के तहत आवेदन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी - हालाँकि, इसे इस सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता है कि प्रतिवादियों को इस तरह के और लाभ दिए जाने से बहुत पहले एक पूर्ण लेनदेन में लाभ का दावा करने के लिए भविष्य में आने वाले बेहतर दावे की प्रतीक्षा की जा सकती थी - वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ इसलिए कि प्रतिवादियों ने स्थलों के आवंटन के लिए आवेदन किया था 10.03.2005 को उनके मामले पर संशोधित प्रोत्साहन नियमों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए जो 27.11.2002 से लागू हुआ, विशेष रूप से उनकी भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी औपचारिकताओं की पृष्ठभूमि में जो पहले ही पूरी हो चुकी थीं - इसके अलावा, प्रतिवादियों ने कभी भी किसी भी प्राधिकारी या यहां तक कि मुआवजे की राशि के समक्ष अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उन्होंने अपनी भूमि को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने के लिए चुना था, जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी, यानी, मूल प्रोत्साहन नियम, और इस प्रकार उस पृष्ठभूमि में वे अपने आचरण और स्वीकृति से बंधे हैं और बाद की तारीख में नियमों में बदलाव के कारण आंदोलन नहीं कर सकते हैं, जो कि चीजों के स्पष्ट होने के बहुत बाद लागू हुआ - 40 फीट x 60 फीट की दो स्थलों और 40 फीट x 30 फीट की दो स्थलों के संबंध में निष्पादित बिक्री विलेख के माध्यम से

प्रतिवादियों को पहले से ही किया गया और हस्तांतरित किया गया आवंटन की पुष्टि की गई है और उन्हें किसी भी आगे के आवंटन का हकदार नहीं माना जाता है। [अनुच्छेद 13,15]

अधिनियमों की सूची

बेंगलोर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1976; बेंगलोर विकास प्राधिकरण (स्वैच्छिक भूमि समर्पण के लिए प्रोत्साहन योजना) नियम, 1989।

प्रमुख शब्दों की सूची

भूमि के स्वैच्छिक समर्पण के लिए प्रोत्साहन योजना; प्रोत्साहन नियम; संशोधित प्रोत्साहन नियम; प्रोत्साहन नियमों के अनुसार स्थलों का आवंटन।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3764/2025
डब्ल्यूए संख्या 1166/2012 में बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.07.2019 से

अधिवक्तागण

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता:
एस. के. कुलकर्णी, एम. गिरीश कुमार, अंकुर एस. कुलकर्णी, सुश्री उदिता चक्रवर्ती, तरुण।
प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता:
राधाकृष्ण एस हेगड़े, राजीव सिंह।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति

अनुमति दी गई।

2. वर्तमान अपील 2012 की रिट अपील संख्या 1166 (एलए-बीडीए) (इसके बाद 'आक्षेपित आदेश' के रूप में संदर्भित) में बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय (इसके बाद 'उच्च न्यायालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 01.07.2019 से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को केवल आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी।

संक्षिप्त तथ्य:

3. बेंगलोर विकास प्राधिकरण (स्वैच्छिक भूमि समर्पण के लिए प्रोत्साहन योजना) नियम, 1989 (बाद में 'प्रोत्साहन नियम' के रूप में संदर्भित) बेंगलोर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1976 (इसके बाद 'बीडीए अधिनियम' के रूप में जाना जाता है) के तहत तैयार किए गए थे। 20.03.1999 को, अधिनियम की धारा 17(1) के तहत एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें अंजनापुरा गांव, उत्तरहल्ली होबली, बेंगलोर में सर्वेक्षण संख्या 71 में 4 एकड़ और 15 गुंटा भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था। बेंगलोर विकास प्राधिकरण (इसके बाद 'बीडीए' के रूप में संदर्भित) द्वारा तैयार की गई एक योजना के तहत अंजनापुरा टाउनशिप के गठन के लिए अन्य भूमि के साथ दक्षिण तालुक प्रतिवादियों से संबंधित है। 31.05.2001 को, प्रतिवादियों ने प्रोत्साहन नियमों के तहत अपनी भूमि के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण का विकल्प चुना और उसी का कब्जा दिनांक 31.05.2001 के महाज़ार के तहत ले लिया गया। इसके अनुसरण में, अधिनियम की धारा 19(1) के तहत एक अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें अन्य भूमियों के साथ-साथ प्रतिवादियों की भूमि भी शामिल थी।

4. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 9 के तहत नोटिस 24.09.2001 को जारी किया गया था। 10.01.2002 को, प्रतिवादियों की भूमि के संबंध में पुरस्कार दिया गया और मुआवजा राशि सिविल न्यायालय में जमा की गई। अधिसूचना दिनांक 09.08.2005 (इसके बाद 'संशोधित प्रोत्साहन नियम' के रूप में

संदर्भित) प्रोत्साहन नियमों में संशोधन और 27.11.2002 से भूमि के स्वैच्छिक समर्पण के लिए पात्रता क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जारी की गई थी। इसके बाद, 10.03.2005 को, प्रोत्साहन नियमों के तहत स्थलों के आवंटन के लिए प्रतिवादियों द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। अपीलकर्ताओं ने 2006 में प्रतिवादियों को दो 40 फीट x 60 फीट स्थलों और दो 40 फीट x 30 फीट स्थलों के संबंध में बिक्री विलेख आवंटित और निष्पादित किया।

5. चूंकि प्रतिवादी संशोधित प्रोत्साहन नियमों के तहत अतिरिक्त क्षेत्र के लिए आंदोलन और मुकदमेबाजी कर रहे थे, अपीलकर्ताओं ने 21.04.2010 को एक समर्थन जारी किया जिसमें कहा गया था कि प्रोत्साहन नियमों के तहत प्रतिवादियों की पात्रता 5400 वर्ग फुट की सीमा तक भूमि के आवंटन के लिए है और 7200 वर्ग फुट की सीमा तक स्थलों का आवंटन पहले ही प्रतिवादियों के पक्ष में किया जा चुका है, जो पहले से ही प्रतिवादियों की तुलना में अधिक है। प्रोत्साहन नियमों के तहत पात्रता।

6. प्रतिवादियों ने दिनांक 21.04.2010 के समर्थन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 28680/2010 (एलए-बीडीए) दायर की। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 08.03.2011 के आदेश के तहत याचिका को स्वीकार करते हुए रिट याचिकाकर्ताओं को संशोधित प्रोत्साहन नियमों के अनुसार प्रतिवादियों को साइट आवंटित करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ताओं ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ 2012 की रिट अपील संख्या 1166 (एलए-बीडीए) दायर की, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई है। ऐसा करते समय, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग के उप सचिव द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.05.2004 पर ध्यान दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि 'ए' खरब भूमि के लिए मुआवजा स्वीकृत किया जा सकता है यदि वे अधिनियम के तहत 4(1) अधिसूचना से पहले प्रदान किए गए थे। हालाँकि, उक्त परिपत्र में कहा गया था कि 'बी' खरब भूमि के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा। विवादित आदेश में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादियों की 4 एकड़ 15 गुंटा भूमि में से 24 गुंटा 'ए' खरब है और 8 गुंटा 'बी' खरब भूमि है, यह माना गया कि प्रतिवादी उस सीमा तक प्रोत्साहन के रूप में किसी भी साइट को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं जो 'बी' खरब है और अपीलकर्ताओं को प्रतिवादियों को 40 फीट x 60 फीट की एक और जगह आवंटित करने का निर्देश दिया।

अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुतियाँ:

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय आक्षेपित आदेश में इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि आवंटन की पात्रता समर्पण की तिथि पर स्पष्ट हो जाती है, न कि आवेदन करने की तिथि पर। इस प्रकार, प्रतिवादियों द्वारा कब्जे के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण की तिथि पर, यानी 31.05.2001 को, प्रोत्साहन नियम प्रचलित और लागू थे। यह तर्क दिया गया कि प्रोत्साहन नियमों के अनुसार, प्रतिवादी 4 एकड़ से अधिक लेकिन 4½ एकड़ से अधिक का क्षेत्र सरेंडर करने पर दो 40 फीट x 60 फीट की साइट और एक 20 फीट x 30 फीट की साइट के हकदार थे।

8. आगे यह तर्क दिया गया कि आक्षेपित आदेश इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि भले ही प्रोत्साहन नियमों के तहत आवंटन के लिए अधिकतम अनुमेय क्षेत्र 40 फीट x 60 फीट की तीन साइटें थीं, जो कुल 7200 वर्ग फीट थीं, लेकिन आत्मसमर्पण किए गए क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी केवल 5400 वर्ग फीट के हकदार थे, जबकि उन्हें वास्तव में 7200 वर्ग फीट आवंटित किया गया था। अंततः यह तर्क दिया गया कि विवादित आदेश में गलती हुई है। प्रोत्साहन नियमों के तहत पात्रता पर विचार नहीं करना और संशोधित प्रोत्साहन नियमों को लागू करना।

प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुतियाँ:

9. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री की सही परिप्रेक्ष्य में सराहना की है और इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादियों ने बिना कोई आपत्ति दर्ज किए स्वैच्छिक से भूमि आत्मसमर्पण कर दी और उन्होंने मुआवजे में कोई वृद्धि नहीं मांगी और केवल प्रोत्साहन नियमों के तहत लाभ मांगा। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता पहले स्थलों को आवंटित करते समय और उनकी पात्रता की गणना करते समय संशोधित प्रोत्साहन नियमों को ध्यान में रखने में विफल रहे थे। तर्क दिया गया कि संशोधित प्रोत्साहन नियमों के प्रावधान प्रभावी रहे हैं दिनांक 27.11.2002 से और इसलिए दिनांक 10.03.2005 को किए गए उनके आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से, पात्रता की गणना संशोधित प्रोत्साहन नियमों के अनुसार की जानी है।

विश्लेषण, तर्क और निष्कर्ष:

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमने पाया कि मामला काफी सरल है। मामले का सार यह है कि क्या 09.11.1989 को अधिसूचित प्रोत्साहन नियम जो 01.04.1989 से लागू हुए या 09.08.2005 को अधिसूचित संशोधित प्रोत्साहन नियम जो 27.11.2002 से लागू हुए, वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू होंगे।

11. घटनाओं का प्रासंगिक क्रम इस प्रकार पुनः बताया गया है:

क) अधिनियम की धारा 17(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना 20.03.1999 को जारी की गई थी जिसमें प्रतिवादियों /उनके पूर्वजों से 4 एकड़ और 15 गुंटा भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था;

ख) प्रोत्साहन नियमों के संदर्भ में, प्रतिवादियों ने 31.05.2001 को अपनी उपरोक्त भूमि के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण का विकल्प चुना और 31.05.2001 को उसका कब्जा भी ले लिया गया;

ग) इसके बाद प्रतिवादियों की भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 19(1) के तहत 04.08.2001 को एक अंतिम अधिसूचना जारी की गई;

घ) तदनुसार, अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस 24.09.2001 को जारी किया गया था, जिसके बाद 10.01.2002 को पुरस्कार दिया गया था, जिसके अनुसार मुआवजे की राशि भी सिविल कोर्ट में जमा की गई थी;

ड) इसके बाद 10.03.2005 को, प्रोत्साहन नियमों के अनुसार स्थलों के आवंटन के लिए प्रतिवादियों द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था; और

च) अपीलकर्ताओं ने वर्ष 2006 में प्रतिवादियों को दो 40 फीट x 60 फीट स्थलों और दो 40 फीट x 30 फीट स्थलों के संबंध में बिक्री विलेख आवंटित और निष्पादित किया।

12. उपरोक्त तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि प्रोत्साहन नियमों के तहत भूमि के अधिग्रहण और स्वैच्छिक समर्पण के साथ-साथ बीडीए अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत कब्जे और अधिसूचना और अधिनियम की धारा 9 के तहत संपूर्ण लेनदेन संशोधित प्रोत्साहन नियमों के प्रभावी होने से बहुत पहले यानी 27.11.2002 को पूरा हो गया था।

13. प्रतिवादियों ने जो लाभ लेना चाहा, वह यह था कि चूंकि उनका आवेदन 10.03.2005 को किया गया था, संशोधित प्रोत्साहन नियम पहले ही लागू हो चुके थे और इस प्रकार संशोधित प्रोत्साहन नियमों के तहत विचार किया जाना चाहिए था, जिससे उन व्यक्तियों को भूमि आवंटन के लिए अतिरिक्त पात्रता का लाभ मिलता था, जिन्होंने स्वेच्छा से प्रोत्साहन नियमों के तहत अपनी भूमि आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुना था। यहां एक पल के लिए रुकते हुए, हम देखेंगे कि प्रतिवादी किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं, जिसे उस दिन से माना जाना चाहिए जब उनकी भूमि के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण का पूरा लेनदेन संबंधित कानून के तहत अधिग्रहण के संदर्भ में पूरा हो गया था, जिसके बाद अधिसूचना और कब्जा सौंपने के साथ-साथ मुआवजा राशि भी जमा की गई थी; यह सब 27.11.2002 से बहुत पहले हुआ था। दरअसल, प्रतिवादी केवल इस कारण से अपना दावा बरकरार रख पाए हैं क्योंकि प्रोत्साहन नियमों के तहत आवेदन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। हालाँकि, इसे इस सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता है कि प्रतिवादियों को इस तरह के और लाभ दिए जाने से बहुत पहले एक पूर्ण लेनदेन में लाभ का दावा करने के लिए भविष्य में आने वाले बेहतर दावे की प्रतीक्षा करनी होगी। वर्तमान मामले में, हमें ऐसा कोई कानूनी मुद्दा नहीं मिला जो प्रतिवादियों को यह दावा करने में मदद कर सके कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने 10.03.2005 को स्थलों के आवंटन के लिए आवेदन किया था, उनके मामले पर संशोधित प्रोत्साहन नियमों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए जो 27.11.2002 से लागू हुआ था, विशेष रूप से उनकी भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी औपचारिकताओं की पृष्ठभूमि में पहले ही पूरा हो चुका था। एक अन्य पहलू जिसका यहां उल्लेख किया जाना आवश्यक है वह यह है कि प्रतिवादियों ने कभी भी किसी भी प्राधिकारी या यहां तक कि मुआवजे की राशि के समक्ष अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उन्होंने जो कुछ भी उन्हें पता था, यानी मूल प्रोत्साहन नियमों के आधार पर स्वैच्छिक रूप से अपनी भूमि को आत्मसमर्पण करने के लिए चुना था, और इस प्रकार उस पृष्ठभूमि में वे अपने आचरण और स्वीकृति से बंधे हैं और बाद में नियमों में

बदलाव के कारण आंदोलन नहीं कर सकते हैं, जो कि चीजों के स्पष्ट होने के काफी बाद लागू हुआ।

14. उपरोक्त पहलू को विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ ने भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। ऐसा कहने के बाद, हम अपीलकर्ताओं द्वारा अपनाए गए रुख के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रतिवादी केवल 5400 वर्ग मीटर के हकदार थे, यानी 40 फीट x 60 फीट के दो प्लॉट और 20 फीट x 30 फीट का एक प्लॉट, जिसका कुल योग 5400 वर्ग फीट होता है और यह प्रोत्साहन नियमों के अनुबंध से स्पष्ट रूप से वहन किया जाता है। हालाँकि, अपीलकर्ताओं द्वारा यह नहीं बताया गया है कि ऐसी पृष्ठभूमि में प्रतिवादियों को 7200 वर्ग फुट कैसे आवंटित किया गया है। जैसा भी हो, चूंकि अपीलकर्ता प्रतिवादियों को पहले से दी गई भूमि की वापसी का दावा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उस पहलू पर जाने से बचते हैं।

15. उपरोक्त कारणों से, हम पाते हैं कि खंड पीठ के आदेश के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार रद्द कर दिया जाता है। 40 फीट x 60 फीट की दो स्थलों और 40 फीट x 30 फीट की दो स्थलों के संबंध में निष्पादित बिक्री विलेख के माध्यम से प्रतिवादियों को पहले ही किए गए और हस्तांतरित किए गए आवंटन की पुष्टि की जाती है और उन्हें किसी भी आगे के आवंटन का हकदार नहीं माना जाता है।

16. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। मूल्य के हिसाब से कोई आदेश नहीं।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति।

शीर्ष टिप्पणियाँ विभूति भूषण बोस द्वारा तैयार की गईं।

यह अनुवाद पैनल अनुवादक (मदन मोहन प्रिय) द्वारा किया गया।